श्री कामाख्या प्रसाद तासा: मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है। नॉर्थ-ईस्ट में कोल का भंडार है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको extract करने के लिए क्या कोल इंडिया सफिशियंट है, क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है? अगर नहीं है, तो क्या प्राइवेट पार्टीज़ को enter करने के लिए कोई व्यवस्था है?

श्री प्रहलाद जोशी : जहां तक नॉर्थ-ईस्ट का सवाल है, मैंने रिसेन्ट्ली असम में विज़िट भी की थी। मैं मणिपुर तक गया था। उधर कुछ NCL का प्रॉब्लम था, उसे भी मैं address कर रहा हूं। कुछ environment issue था, I had a talk with hon. Minister Shri Prakash Javadekar, he is kind enough to give all the clearances. Now, it is re-opening और मणिपुर में एक है। मणिपुर में coal was already produced but because of that rat-hole mining, it was stopped by the hon. Supreme Court. Now, the clearance has been given. I would like to tell one thing. Wherever coal is available, either Coal India would do it or we would go for the action, that would be decided by the Coal Ministry from time to time.

स्टेडियमों का निर्माण

* 231. **श्री सतीश चंद्र दुबे**: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर स्टेडिया के निर्माण सहित खेल अवसंरचना प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर किसी स्टेडिया के निर्माण का कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Construction of stadia

†*231. SHRI SATISH CHANDRA DUBEY: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

1.00 P.M.

(a) whether it is a fact that Government had decided to build stadia at the State, district and panchayat levels to promote sports in the country; and

(b) if so, the progress made in this regard so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) 'Sports' being a State subject, the responsibility for providing sports infrastructure, including construction of stadia at State, district and panchayat levels, rests with the State/Union Territory (UT) Governments. Central Government supplements efforts of the State Governments. There is no proposal under consideration of the Central Government to build any stadia at State, district and panchayat levels.

श्री सतीश चंद्र दुबे: मंत्री जी पूरे भारत का 70 प्रतिशत आबादी गांव में, देहातों में, छोटे-छोटे शहरी कस्बों में रहती है। बहुत से प्लेयर जो होनहार हैं, देश के भावी भविष्य हैं, क्या उन लोगों को निकालने के लिए, उन लोगों के लिए जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर खेल कार्यक्रम कराकर और उनको चयनित करने के लिए सरकार के पास कोई नई योजना है या नहीं?

श्री किरेन रिजिजु: मैडम, योजनाएं तो बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और खेलो इंडिया कार्यक्रम, जिसकी प्रधान मंत्री जी ने कल्पना की थी, उसे हम आगे गांव-गांव तक ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त लगभग 15,000 खिलाड़ी हमारे विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिल हैं और उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस चल रही है। हमारा सपना भारत को खेल के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाना है। इसमें जो गांव की बात कही गई है, इसके लिए हमने टेलेंट सर्च कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। जो ऐसे गांव हैं, जो ऐसे potential areas हैं - जैसे हमारे माननीय सदस्य बिहार से आते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाकर के छोटी उम्र के, कम उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करके, उनका सेलेक्शन करना है और फिर उनको प्रशिक्षण देना है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इसके साथ ही साथ मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि बिहार में कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो पाया, तो हमने बिहार सरकार से कहकर के...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): क्वेश्वन ऑवर का समय समाप्त हो चुका है। सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।